



2026: AHC: 26030

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 506 वर्ष 2026

सोचन एवं अन्ययाची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रतिवादीगण

याची के अधिवक्ता: अजय कुमार सिंह, सरिता सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. याचियों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा बोर्ड पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. यह रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:
"क) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को निगरानी संख्या 1166/24-25 (रमेश बनाम बेचन एवं अन्य), अंतर्गत धारा 48 (1) यू.पी.सी.एच. एक्ट, ग्राम बरईखुर्द, परगना गोपालपुर, तहसील मड़ियाहूँ, जिला जौनपुर को कानून के अनुसार एक विशिष्ट अवधि के भीतर तय करने का निर्देश दिया जाए।"
3. यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त मामला काफी लंबे समय से विचार के लिए लंबित है; हालाँकि, इसे शीघ्रता से तय कराने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त मामले के त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश जारी किया जाता है।
5. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है, जिसमें वर्तमान रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, उप संचालक चकबंदी (प्रतिवादी संख्या 2), जिनके समक्ष उपरोक्त मामला निस्तारण हेतु लंबित है, को निर्देश दिया जाता है कि वे कानून के अनुसार इसे शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से पांच महीने की अवधि के भीतर तय करें, यदि कोई अन्य कानूनी बाधा न हो।
6. उपरोक्त निर्देश के साथ, वर्तमान आवेदन निस्तारित किया जाता है।

फरवरी 5, 2026

विनय

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"